

समाजवादी बुलेटिन



22 में बाइसिकल

लाल टोपी से भाजपा के नेता परेशान हो गए हैं। भाजपा को लाल टोपी से अपने लिए खतरा लग रहा है। लाल टोपी भाजपा के कुशासन के खिलाफ रेड अलर्ट है। लाल टोपी व्यवस्था परिवर्तन में अहम योगदान देगी। भविष्य समाजवादियों का है।

मुलायम सिंह यादव

मुलायम सिंह यादव
संस्थापक-संरक्षक, समाजवादी पार्टी



समाजवादी बुलेटिन

जनवरी 2022
वर्ष 23 | संख्या 03

प्रिय पाठकों,

नव वर्ष की हार्दिक
शुभकामनाएं!
आपकी प्रिय पत्रिका
समाजवादी बुलेटिन बदले
हुए कलेवर में अपने दूसरे
वर्ष में प्रवेश कर चुकी है।
आपके उत्साहवर्धन और
प्रेम के कारण ही हमारा
यह सफर यहां तक पहुंचा
है। हम भरोसा दिलाते हैं
कि हम आपकी उम्मीदों
पर खरा उतरने की अपनी
कोशिशों में कोई कमी नहीं
आने देंगे। कृपया हमेशा
की तरह आगे भी हमारा
मार्गदर्शन करते रहें।
धन्यवाद!

प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक
प्रोफेसर रामगोपाल यादव

☎ 0522 - 2235454

✉ samajwadibulletin19@gmail.com

✉ bulletinsamajwadi@gmail.com

Mob:- 9598909095

📌 /samajwadiparty

समाजवादी पार्टी के लिए

19, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ से प्रकाशित
अवध पब्लिशिंग हाउस, 8 पान दरीवा, लखनऊ से मुद्रित

R.N.I. No. 68832/97

अंदर



रामपुर : जनता लड़ रही आजम साहब का चुनाव

42

06 कवर स्टोरी

22 में बाइसिकल



भाजपा राज में बढ़ गई बेरोजगारी

युवा 38



सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक बीते पांच साल में उत्तर प्रदेश में नौकरी करने वालों की तादाद 16 लाख 13 हजार घट गयी है।

रेलवे भर्ती परीक्षा नतीजों का व्यापक विरोध, इलाहाबाद पुलिस ने लॉज में घुसकर छात्रों को पीटा

सत्यमेव जयते ही समाजवादियों की ताकत

28

पोस्टल बैलेट: नई व्यवस्था में सतर्क रहें कार्यकर्ता

34



प्रिय देश-प्रदेशवासियों

‘गणतंत्र दिवस’ की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं !

आइए इस गणतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि जिस संविधान ने इस महान गणतंत्र की स्थापना की है उसे हर हाल में बचाएंगे। आज संविधान संकट में है और कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हावी हो रही हैं, जो अपने मनमाने विधान से देश को चलाना चाहती हैं। आइए अपने देश और अपने देशवासियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए हम उस पॉज़िटिव, प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स की ओर बढ़ें जो किसी एक खास वर्ग को नहीं बल्कि आम जनमानस को संग लेकर बढ़ती है, समता-समानता लाने के लिए भेदभाव मिटाती है और सम्पन्नता को हर घर-द्वार तक पहुँचाती है, जिसका हर काम आम जनता को समर्पित होता है, जिसकी दिशा समाज के निम्नतम स्तर पर जीवन जी रहे व्यक्ति से ऊपर की ओर होती है। जिसके मूल में आम जनता के ‘कल्याण’ की भावना होती है; न कि कुछ लोगों के ‘लाभ’ की।

‘आधी कमाई और दोगुनी महँगाई’ के इस दौर में बेकारी और दमन का मारा गरीब और शोषित वर्ग ही नहीं बल्कि सड़क पर आ गया मज़दूर और कुशल, अर्द्ध-कुशल श्रमिक व हनरमंद कारीगर, पढ़े-लिखे बेरोज़गार युवक व युवतियाँ, अर्थव्यवस्था की बदहाली की वजह से नौकरी से निकाले हुए लोग, रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर छोटे, लघु व बड़े कारोबारी, व्यापारी और उद्योगपति भी परेशान हैं तो गाँवों में आवारा पशुओं से किसान भी, दरअसल जब से वर्तमान सरकार आई है सिर्फ़ मुश्किल-परेशानी लाई है।

इस सरकार में किसानों, मजदूरों, पिछड़ों, दलितों, महिलाओं, युवाओं, शिक्षाकर्मियों, स्वास्थ्यकर्मियों और काम-कारोबारी, प्रोफेशनल्स को ‘दिवक्रत, क्रिल्लत और ज़िल्लत’ के सिवा कुछ नहीं मिला है। इस सरकार ने समाज के दो स्पष्ट हिस्से कर दिये हैं, एक तरफ़ लगातार धन-संपन्न होते लोग हैं; दूसरी तरफ़ निरंतर निर्धन होते लोग। धनी वर्ग में भी कुछ गिने-चुने ही धनसंचय के कीर्तिमान बना रहे हैं। मध्यवर्ग मध्य में पिस रहा है, जिस बचत-ब्याज पर उसका भविष्य निर्भर करता है वह बैंकों तक में सुरक्षित नहीं है। वैसे तो बचत ही ही नहीं रही है और जो पहले से बैंकों में जो बचा-खुचा जमा है उस पर नाम मात्र का ब्याज ही मिल रहा है, जो धीरे-धीरे घटकर शून्य ब्याज दर तक पहुँच सकता है। इसका शिकार वो बुज़ुर्ग भी हैं जिनका जीवन यापन व दवा-इलाज का खर्चा ब्याज से मिलनेवाले पैसों से ही होता है।

इसीलिए हम अपने जन कल्याण के मूल मंत्र ‘सपा का काम ~ जनता के नाम’ के तहत जनता को राहत देने वाली योजनाओं की निरंतर घोषणाएँ कर रहे हैं। इन योजनाओं पर होने वाले खर्चों को हम खर्चा या एक्स्पेंडिचर नहीं बल्कि निवेश या इन्वेस्टमेंट मानकर चल रहे हैं क्योंकि जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वही पैसा अर्थव्यवस्था के चक्के को घुमाएगा, तब ही सबको काम और उनके काम का सही दाम मिल पाएगा। जब बड़े-बड़े उद्योगपतियों को छूट दी जा सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं! 300 यूनिट फ्री घरेलू बिजली, मुफ्त सिंचाई, सभी फसलों के लिए एमएसपी, गन्ना किसानों को 15 दिन में सुनिश्चित भुगतान, ब्याज मुक्त ऋण, बीमा, पेंशन; 18000 सालाना की समाजवादी पेंशन; प्रतिभावान को लैपटॉप; आईटी सेक्टर में 22 लाख रोज़गार व अन्य लाखों सरकारी व अन्य रिक्त पदों को भरने; पुरानी पेंशन को बहाल करने, कैशलेस इलाज व जाति गणना जैसे सामाजिक-आर्थिक प्रयासों के साथ ही हम किसानों के जान-मान की रक्षा के लिए ‘अन्न संकल्प’ भी ले रहे हैं।

हम अपने सिद्धांत ‘अनुशासन से शासन’ के तहत कारगर क़ानून-व्यवस्था को बहाल करने के लिए असामाजिक आपराधिक तत्वों, सामाजिक विद्वेष व नफ़रत फैलानेवालों के साथ ही, वर्तमान सरकार में बेलगाम हुई पुलिस व्यवस्था को संरचनात्मक व संस्थागत सुधारों से फिर से पटरी पर लाने के लिए 100% वचनबद्ध हैं। ये हमारा संकल्प है कि किसी की भी अराजकता, किसी भी रूप में सही नहीं जाएगी।

वर्तमान निर्दयी सरकार में हुए हाथरस, लखीमपुर, उन्नाव, गोरखपुर, आगरा व अन्य जगह हुए क्रूर कांड; बेरोज़गार पर बेरहमी से अनगिनत बार लाठीचार्ज, व्यापारियों से वसूली व हत्या; युवाओं और विपक्ष पर झूठे मुकदमों; बलात्कारों, दलितों-पिछड़ों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार; वसूलीवाले पुलिस कप्तान के फ़रार होने व इनामी अपराधी के सरेआम खेलने जैसे निंदनीय कृत्यों व कोरोना की बदइंतज़ामी में ऑक्सीजन तक के लिए बोले गये झूठ व गंगा जी तक में बहती लाशों जैसे शर्मनाक दृश्यों से उग्र की छवि अब और ख़राब नहीं होने दी जाएगी। अच्छे पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को अच्छी कार्य दशाएँ, व्यवस्थाएँ व अधिक मान-सम्मान पदक देंगे। ऐसे प्रयासों से ही प्रदेश की हर माँ, बहन, बेटी, बहू व आम जनता व व्यापारी-निवेशक अपने को सुरक्षित महसूस करेगा। 'यशभारती' सम्मानों की बहाली व नये 'नगर-भारती' सम्मान-पत्रों के माध्यम से हम समाज के विभिन्न वर्गों के योगदान का भी मान-सम्मान करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि सभी के सहयोग से ही हम 'नव उग्र' या 'न्यू यूपी' के निर्माण के लिए और उसके चतुर्दिक विकास के लिए काम कर सकते हैं। इसीलिए हम एक बार फिर से दोहराते हैं: है जनसेवकों के लिए सपा का ये ऐलान ~ सब आएँ, सबको स्थान, सबको सम्मान

'सम्पर्क, संवाद, सहयोग, सहायता' अर्थात 'मुलाक़ात, मेल-मिलाप, मदद' का 'जनसेवा-सूत्र' हम एक संकल्प के रूप में याद रखें और ये संकल्प दोहराएँ: पहुँचें हर घर-द्वार ~ सपा के मददगार

आइए 'बाइस में बाइसिकल' का संकल्प धारण कर आगे बढ़ें और जनता की खुशी-खुशहाली और भलाई के लिए काम करने वाली सपा के नेतृत्ववाली जनहितकारी और परिवारवालों का दर्द समझनेवाली, सपा-सहयोगियों की सरकार बनाने के लिए गर्व से कहें:

नयी हवा है ~ नयी सपा है

बड़ों का हाथ ~ युवा का साथ

बड़ों के आशीर्वाद और युवाओं के साथ का आकांक्षी...

आपका अखिलेश

अखिलेश
सपा



उ

त्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव शुरू हो चुके हैं और शुरुआत के साथ ही समाजवादी पार्टी गठबंधन को जनता के अभूतपूर्व समर्थन का संकेत पूरे प्रदेश से मिलने लगा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के एक साथ आने और सत्ता परिवर्तन का जो आह्वान किया है उसके प्रति जनता से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है।

श्री अखिलेश यादव की कामयाब विजय यात्राओं और मजबूत चुनावी गठबंधन ने जनता के मिजाज की झलक पहले ही दे रखी थी।

चुनाव की घोषणा के बाद जिस तरह से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनता समाजवादी गठबंधन के पक्ष में मुखर हो रही है उससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है और समाजवादी गठबंधन बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है।

पश्चिम से लेकर पूरब और अवध से लेकर बुंदेलखंड एवं रुहेलखंड तक जो माहौल है उससे स्पष्ट संदेश निकल रहा है कि श्री अखिलेश यादव द्वारा दिया गया 22 में बाइसिकल का नारा 2022 के विधानसभा चुनाव में सही साबित होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रति बन रहे जबरदस्त माहौल को इससे भी समझा जा सकता है कि विभिन्न दलों के कद्दावर नेता

अपनी पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। समाज के हर वर्ग से समाजवादी पार्टी गठबंधन के सामाजिक न्याय के वादे को समर्थन मिल रहा है।

प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जनता समाजवादी गठबंधन के पक्ष में मुखर हो रही है। उससे स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार सत्ता परिवर्तन तय है और समाजवादी गठबंधन बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाने की ओर अग्रसर है

श्री अखिलेश यादव ने न सिर्फ गठबंधन का बहुरंगी ताना-बाना बुना है बल्कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जो घोषणाएं वे कर रहे हैं, उनसे भी लग रहा है इस बार साइकिल सरपट दौड़ेगी। इन घोषणाओं में सरकार बनने पर घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को प्रति महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली,

सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली, गरीब तबके को ₹18000 सालाना समाजवादी पेंशन, किसानों को मुफ्त सिंचाई, छात्रों नौजवानों को मुफ्त लैपटॉप और आईटी के क्षेत्र में 22 लाख से ज्यादा नौकरियां उपलब्ध कराने की घोषणाएं प्रमुख हैं।

इन घोषणाओं के बाद जनता के मन में समाजवादी गठबंधन को सरकार में लाने का संकल्प और मजबूत हुआ है। जमीन खिसकती देख सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी समाज को बांट कर वोट पाने की अपनी पुरानी शैली को आजमाने में जुट गई है लेकिन जनता ने इस बार मन बना लिया है कि किसी कीमत पर इस अयोग्य और अनुपयोगी सरकार को सत्ता से हटाकर समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनानी है।

जनता के समर्थन और आशीर्वाद से बन रहे माहौल से साफ है कि 22 में बाइसिकल का नारा अपने अंजाम तक पहुंचेगा और पुनः एक बार श्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर अपनी दूरदृष्टि और मजबूत इरादों के साथ उत्तर प्रदेश को फिर एक बार प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे। हर जाति, हर वर्ग, हर आयु और राज्य के हर क्षेत्र की जनता चाहती है कि उत्तर प्रदेश में फिर एकबार विकास और सामाजिक भाईचारे को प्राथमिकता देने वाली सरकार बने और विकास को रोकने एवं समाज को बांटने वाली सरकार से प्रदेश को मुक्ति मिले।

22 में बाइसिकल



22 नें वाइसिकल

सेवा को सम्मान
पुरानी पेंशन योजना होगी

समाजवादी पार्टी
2005 से फ

समाजवादी पार्टी का संकल्प
समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर
छात्रों एवं नौजवानों को निशुल्क लैपटॉप

समाजवादी सरकार में 20 लाख से अधिक
लैपटॉप वितरित किए गए हैं

बुद्धि को मिलेगी अविनाशनीय परीक्षा से निजा
साइकिल के साथ

किसान को हक़ और सम्मान
समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर
किसानों को मिलेगी मुफ्त सिंचि

22 नें वाइसिकल

अखिलेश जी का संकल्प
फिर शुरू होगी समाजवादी पेंशन

संत लखिमपुर, BPL
प्रति वर्ष 18000र पेंशन
सरकार में किया

22 नें वाइसिकल

किसान की शह

समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसानों के लिए
25-25 लाख रुपए
और उनके
किसान रक्षा

समाजवादी पार्टी का संकल्प
समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर घरेलू

**300 यूनिट
फ्री बिजली**

अब उत्तर प्रदेश
उन्नति का

किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी

दूरदृष्टि, पक्का इरादा

सरकार वही जो जनता के हितों की रक्षा करें। जो जनता के दुख दर्द को अपना कष्ट समझे और उनका समाधान करें। ऐसी सरकार चलाने के लिए जिस दूरदृष्टि और पक्के इरादे की जरूरत होती है उसकी मिसाल हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर जनता के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली, कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली, छात्रों को मुफ्त लैपटॉप और गरीब परिवारों को समाजवादी पेंशन जैसी घोषणाएं श्री अखिलेश यादव की दूरगामी सकारात्मक सोच का ही नतीजा हैं। पेश है इन खास घोषणाओं पर विशेष रिपोर्ट:

बुलेटिन ब्यूरो

स

माजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश मुख्यालय लखनऊ पर हजारों की संख्या में आए नेताओं और समर्थकों को नववर्ष की बधाई देते हुए दिनांक एक जनवरी को घोषणा की कि प्रदेश में समाजवादी सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री और किसानों को सिंचाई पूरी तरह मुफ्त करेंगे।

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी लोगों की कथनी और करनी एक है। जनता यह भलीभांति जानती है। समाजवादी लोग जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। नया साल 2022 के पहले दिन समाजवादी पार्टी का जनता से यह पहला संकल्प है।

उन्होंने कहा कि भाजपा झूठ बोलने और वादाखिलाफी के लिए जानी जाती है। भाजपा जनता का भरोसा खो चुकी है। श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने जनता



को 2021 में बहुत दुःख और परेशानी दी है। लोगों पर फर्जी मुकदमें लगाकर प्रताड़ित किया। सबसे ज्यादा झूठे मुकदमें समाजवादियों पर लगाए गए हैं। श्री यादव ने कार्यकर्ता और नेताओं से कहा कि वे चुनाव में अपना अपना बूथ जिताकर पार्टी को भेंट दे। यहीं नववर्ष की असली बधाई होगी।

श्री अखिलेश यादव ने प्रदेश में '300 यूनिट मुफ्त बिजली पाओ, नाम लिखाओ' अभियान की 18 जनवरी को घोषणा करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर-घर जाकर इस अभियान का फॉर्म भराएंगे। इसमें कोई छूटे नहीं। यह अभियान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी चलेगा। उनकी घोषणा के मुताबिक सपा के कार्यकर्ता घर-घर जाकर इस अभियान में जुटे हुए हैं।

श्री अखिलेश यादव ने अपील की कि जिन

लोगों के पास बिजली का कनेक्शन है, वह उसी नाम से फॉर्म भरें, जिस नाम से बिजली कनेक्शन है। जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है वह राशन कार्ड या आधार कार्ड में उल्लेखित नाम लिखाएं।

छात्रों-नौजवानों को मिलेगा लैपटॉप

श्री अखिलेश यादव ने 8 जनवरी को घोषणा की कि समाजवादी सरकार बनने पर हम नौजवानों, छात्रों को पहले की तरह फिर लैपटॉप देंगे।

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने लगभग 20 लाख छात्र नौजवानों को लैपटॉप दिए, जो आज भी चल रहे हैं। भाजपा सरकार ने जो टेबलेट दिए हैं उन पर सवाल उठ रहे हैं।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार केवल झूठे प्रचार पर चल रही है। भाजपा के लोग झूठ बोलते हैं। भाजपा सबसे झूठी पार्टी है। मुख्यमंत्री जी अपने सारे आयोजन और कार्यक्रम समाजवादी सरकार के बनाए स्टेडियम में करते हैं। उनके पास अपना काम बताने के लिए कुछ नहीं है। जनता बहुत नाराज है वह इस बार भाजपा का सफाया करेगी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार बनने पर 69000 शिक्षक भर्ती के साथ-साथ शिक्षामित्र, अनुदेशक, एंबुलेंस कर्मी ड्राइवर, सभी की मदद की जाएगी उन्होंने कहा कि धरना-प्रदर्शन कर रहे नौजवान अब धरना देना बंद करें। अपमानित ना हो, अपने बूथ पर जाएं और भाजपा को हराने का काम करें, सरकार बनते ही समाजवादी पार्टी सभी को सम्मान देगी।



फाइल फोटो



फाइल फोटो

समाजवादी पेंशन

बढ़कर 18 हजार होगी

श्री अखिलेश यादव ने समाजवादी सरकार बनने पर फिर से समाजवादी पेंशन योजना शुरू करने की 19 जनवरी को घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस बार जरूरतमंद गरीब परिवार की महिलाओं को प्रतिवर्ष 18 हजार रुपए पेंशन दी जाएगी। श्री यादव ने कहा कि पिछली बार सपा सरकार के दौरान 50 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन योजना में 6 हजार रुपए वार्षिक का लाभ दिया जा रहा था। लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे पैसा पहुंचाया जा रहा था।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में वाराणसी, कुशीनगर में मुसहर जाति के गरीब लोगों को लोहिया आवास और पेंशन दी थी। ललितपुर में

गरीबों को पेंशन एवं आवास दिया था। लखनऊ में पी.जी.आई. के पास और कन्नौज में सपेरों को पेंशन और लोहिया आवास दिया गया। सरकार बनने पर एक्सप्रेस-वे के किनारे सपेरा गांव भी बसाया जाएगा।

पुरानी पेंशन बहाल होगी

श्री अखिलेश यादव ने 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए 2005 से पहले की पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का वादा किया है। श्री यादव ने 19 जनवरी को यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि आर्थिक पहलुओं पर मंथन के बाद पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला किया गया है।

श्री अखिलेश यादव ने विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले यश





फाइल फोटो

भारती सम्मान को फिर शुरू करने और जिला स्तर पर नगर भारती सम्मान दिए जाने की घोषणा भी की।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने कर्मचारियों और शिक्षकों की पुरानी पेंशन को खत्म कर दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर हम इसे पुनः बहाल करेंगे। लम्बी सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के जीवन निर्वाह के लिए पुनः पुरानी सामाजिक सुरक्षा पेंशन दिया जाना उचित है।

भाजपा ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों के साथ धोखा किया। पेंशन बहाली से 13.37 लाख लोग लाभाविन्त होंगे। राज्य कर्मचारियों और अटेवा संगठन की इस सम्बंध में पुरानी मांग रही है। कर्मचारियों के इलाज के लिए कैशलेस स्कीम को लागू किया जाएगा।

श्री यादव ने वित्तविहीन शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देने की व्यवस्था करने का भी आश्वासन दिया। श्री यादव ने कहा कि भाजपा कर्मचारी विरोधी है। हर वर्ग को धोखा दिया है। भाजपा सरकार भेदभाव के साथ काम करती रही जबकि समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में कोई अंतर नहीं है। हमने जो भी वादा किया उसको पूरा किया है।

आउटसोर्सिंग को लेकर श्री यादव ने कहा कि

यह अच्छी प्रथा नहीं है, इसमें शोषण के अलावा कुछ नहीं होता है। भाजपा सरकार ने कर्मचारियों की बात नहीं सुनी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार कर्मचारियों, शिक्षकों, आंगनबाड़ी सभी की समस्याओं का समाधान करेगी। भाजपा यदि सरकार में रही तो हर चीज बेच देगी। भाजपा एक दिन सरकार को भी आउटसोर्स कर देगी। समाजवादी पार्टी निजीकरण के खिलाफ है। भाजपा ने निजीकरण के जरिए संविधान और आरक्षण को नुकसान पहुंचाया।

श्री अखिलेश यादव से अटेवा-पेंशन बचाओ मंच के प्रतिनिधिमण्डल ने 20 जनवरी को भेंट कर उन्हें पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा के लिए धन्यवाद दिया और आभार व्यक्त किया।

आईटी क्षेत्र में मिलेंगी

22 लाख नौकरियां

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दिनांक 22 जनवरी को घोषणा की कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर 'नौकरी-रोजगार संकल्प श्रृंखला' में आईटी सेक्टर में 22

लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लखनऊ से आगे कानपुर, आगरा, बरेली, झांसी, वाराणसी और पूर्वांचल में भी आईटी हब बनाएगी और 22 लाख से अधिक नौजवानों को आईटी सेक्टर में नौकरी दिलाने का वायदा पूरा करेगी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि नौकरियों को लेकर अभी हमने सिर्फ आईटी सेक्टर की बात कही है। सरकारी और अन्य क्षेत्रों की नौकरियां अलग होंगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह 22 लाख नौकरियां पुलिस, शिक्षक एवं अन्य सरकारी विभागों में भर्ती के अलावा होंगी।

उन्होंने कहा कि पहले आईटी सेक्टर नोएडा और गाजियाबाद के आस पास ही था लेकिन समाजवादी सरकार ने पहली बार लखनऊ में आईटी सिटी का निर्माण कराया। एचसीएल जैसी कंपनी यहां आई जिसमें आईटी सेक्टर के 5 हजार इंजीनियरों को नौकरी मिली। समाजवादी सरकार इसे और आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन भाजपा सरकार ने इस पर कोई काम नहीं किया। विकास कार्यों को रोका है।



विजयी भव

उन्नाव-लखनऊ की विजय यात्राओं में भीड़ का रेला



बुलेटिन ब्यूरो

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की दिनांक 28 दिसंबर 2021 को उन्नाव एवं दिनांक 2 जनवरी को लखनऊ जनपदों में हुई विजय यात्राएं खासी कामयाब रहीं। दोनों यात्राओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ी। लखनऊ की विजय यात्रा के दौरान श्री अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के गोसाईगज के पास स्थित महराकलां गांव में नवनिर्मित भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना के साथ

आरती की। मंदिर में पूजा-आरती के बाद उपस्थित साधु-संतों, आचार्यों ने श्री अखिलेश यादव का तिलक कर विजयी होने का आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि श्री यादव ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। श्री अखिलेश यादव 28 दिसंबर को समाजवादी विजय रथ यात्रा के नौवें चरण में जनपद उन्नाव पहुंचे। उन्होंने वहां विधान सभा क्षेत्र उन्नाव के जीआईसी ग्राउंड के बाद सफीपुर, बांगरमऊ तथा मोहान विधानसभा

क्षेत्र में जनसभाओं में विशाल जनसमुदाय को सम्बोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं समेत जनता के मुद्दों और सवालियों से बचने के लिए लगातार झूठ बोल रही है। विधानसभा चुनाव में किसान, नौजवान और व्यापारी भाजपा सरकार को हटा कर झूठ बोलने वालों का पर्दा हटाएगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि आज महंगाई बहुत बढ़ गई है। किसानों, गरीबों को महंगी बिजली मिल रही है। भाजपा









सरकार गरीबों को धोखा दे रही है। जिस तरह की महंगाई है उससे कमाई आधी हुई है। खाद की बोरी में चोरी हो रही है। सपा सरकार बनने पर किसानों की मदद करेंगे। नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार का इंतजाम करेंगे। सांड के हमले से जिन लोगों की मौत हुई है, उनको 5 लाख रुपया देंगे। साइकिल दुर्घटनाओं में मरे हुए लोगों को भी 5 लाख की आर्थिक मदद देंगे।

श्री यादव ने मुख्यमंत्री को झूठा करार देते हुए कहा कि योगी और भगवाधारी झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी से बड़ा झूठा कोई नहीं है। इन्होंने ऑक्सीजन से कमी से हुई मौतों पर भी झूठ बोला। यह प्राणघातक सरकार है। श्री यादव ने कहा कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास समाजवादी सरकार में हुआ था। कानपुर की जनता को मेट्रो के लिए बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनेगी तो मेट्रो कानपुर से गंगा

पार कर उन्नाव तक लाएंगे। श्री अखिलेश यादव ने दिनांक 2 जनवरी को समाजवादी विजय रथ यात्रा के दसवें चरण में लखनऊ जनपद के एच.सी.एल. आई.टी. चकगंजरिया से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के किनारे महुराकला गांव में नवनिर्मित भगवान परशुराम जी के मंदिर तक यात्रा की। इस दौरान रास्ते भर भारी जनसमुदाय ने जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया। उन्होंने आई.टी. सिटी चकगंजरिया, रोहतास के मैदान और करीमपुर में विशाल जनसभाओं को सम्बोधित किया। अमूल दुग्ध प्लांट के पास बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने झण्डे बैनर और पोस्टर के साथ स्वागत किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के पास समाजवादी विजय रथ यात्रा का स्वागत अखिलेश यादव जिंदाबाद के जोरदार नारों के साथ हुआ। अपने संबोधन में श्री अखिलेश यादव ने

कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश को पीछे धकेल दिया है। भाजपा राज में हर वर्ग अपमानित और प्रताड़ित किया जा रहा है। अब नए वर्ष में उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। सभी लोग बदलाव चाहते हैं। समाजवादी सरकार ने उत्तर प्रदेश को विकास और रोजगार का मॉडल दिया। लखनऊ में आई.टी. सिटी की स्थापना की, अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय स्टेडियम दिया, एक्सप्रेस वे बनाया, पार्क, कैसर इंस्टीट्यूट दिया। भाजपा सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है।

श्री अखिलेश यादव ने जनसभाओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसान भाजपा सरकार के अन्याय और अत्याचार को कभी नहीं भूल सकता है। भाजपा के लोगों ने किसानों की जीप से कुचलवा कर हत्या करा दी। भाजपा सरकार में किसानों



की आय दोगुनी नहीं हुई। नौजवानों को रोजगार और नौकरी नहीं मिली। जबकि सपा सरकार ने राजधानी लखनऊ में विकास के लिए बहुत कार्य किए। सपा के प्रति जिस तरह का समर्थन दिखाई दे रहा है वह ऐतिहासिक बदलाव के संकेत हैं।

यात्रा के दौरान महुराकलां गांव में नवनिर्मित भगवान परशुराम मंदिर में परशुराम भगवान की जय और नमः शिवाय के नारों के बीच श्री अखिलेश यादव ने पूजा और आरती की। उन पर फूलों की वर्षा की गई। श्री अखिलेश यादव ने 68 फिट ऊंचे भगवान परशुराम के फरसे को भी पुष्पांजलि अर्पित की तथा आरती की। मंदिर के भव्य कार्यक्रम में जहां काशी के डमरू दल के 101 युवा डमरू ध्वनि कर रहे थे वहीं काशी, मथुरा, अयोध्या और प्रयागराज से आए साधु संत, मंत्रोच्चार कर रहे थे। 551 वेद पाठी ब्राह्मण अलग वैदिक मंत्रोच्चार कर रहे थे। साथ ही शंख ध्वनि से वातावरण गुंजित था।





फाइल फोटो

अखिलेश यादव

सभी वर्गों के स्वाभिमान के पर्याय



रामगोविन्द चौधरी

नेता प्रतिपक्ष

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव युवा, छात्र, गरीब, मजदूर, किसान, अतिपिछड़ा, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखने वाले सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों के स्वाभिमान के पर्याय हैं। हिटलरी गुमान के समर्थक भाजपाई उनपर ओछी टिप्पणी करने से बाज आएँ नहीं तो उत्तर प्रदेश में भाजपा के खाते से विधायक शब्द लुप्त हो जाएगा।

भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को अपने आंतरिक सर्वे में यह सत्य पता चल गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में अखिलेश यादव जनता की पसंद हैं और वह सत्ता में आ रहे हैं। दस मार्च को इसकी विधिवत घोषणा हो जानी है। इसी वजह से

लाठी मार पार्टी भाजपा हताश है। इसी हताशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या की जगह भग कर गोरखपुर की शरण में गए हैं।

पूरा प्रदेश मंहगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी उत्पीड़न से त्राहि त्राहि कर रहा है। लोग खुद इस सरकार से पिंड छुड़ाने के लिए बेताब हैं। विधानसभा के समक्ष दौड़ा-दौड़ा कर पीटे गए शिक्षक, कर्मचारी, देश में पहली बार महिला शिक्षामित्तों के मुण्डन कराया, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं जवाब देने के लिए अपने अपने गांव में भाजपाइयों का इंतजार कर रहे हैं।

किसान अपने साथी सैकड़ों शहीद किसानों की मौत का हिसाब अपने वोट से चुकता करने को बेताब है। सरकारी तंत्र, विज्ञापन के बल पर यह साबित करने में लगा है कि चारों तरफ खुशी व्याप्त है। दस मार्च को यह

घोषणा हो जाएगी कि सभी वर्गों के लोगों के स्वाभिमान के प्रतीक श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत प्राप्त हो गया।

पूरे प्रदेश में सपा और उसके सहयोगी दलों की लहर चल रही है। भाजपा के लोग इससे बचने के लिए अफवाह फैलाएंगे, नफरत फैलाएंगे। इसके मुकाबले के लिए हम लोगों को बस एक नारा याद रखने की जरूरत है कि "अपना बूथ जिताएंगे, अखिलेश को सीएम बनाएंगे।"

कुछ अधिकारी और कर्मचारी भाजपा के वर्कर की तरह काम कर रहे हैं। ऐसे अधिकारियों, कर्मचारियों पर नज़र रखिए और इनकी हर गलत हरकत की शिकायत चुनाव आयोग एव पार्टी नेतृत्व को तत्काल भेजिए।





भाजपा को हटाने और हराने के लिए 'अन्न संकल्प'

बुलेटिन ब्यूरो

स माजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को हटाने और हराने के लिए "अन्न संकल्प" लिया है। सपा प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में घायल किसान नेता श्री तेजिंदर सिंह बिर्क के साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव और अन्य नेताओं ने दिनांक 17 जनवरी को भाजपा को हटाने और हराने का "अन्न संकल्प" लिया। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने पार्टी के सभी नेताओं और किसानों से अपील की



कि वे सब अन्न संकल्प लें कि किसानों पर अत्याचार और अन्याय करने वाली भाजपा सरकार को हटाएं और हराएं।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में श्री तेजिंदर सिंह बिर्क को कुचल देने की साजिश थी। घटना में श्री बिर्क गम्भीर रूप से घायल हुए। किसानों, नेताओं ने इन्हें अस्पताल पहुंचाया, इलाज हुआ और भगवान ने बचा लिया।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि श्री तेजिंदर सिंह बिर्क ने किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और संघर्ष किया। किसानों ने अपने संघर्ष से भाजपा सरकार को झुका दिया। भाजपा सरकार ने जो तीन काले कानून किसानों पर थोपे थे, उससे खेती बर्बाद हो जाती, जमीन छिन जाती, किसान बर्बाद हो जाता, फसलों का कंट्रोल दूसरों के हाथ में चला जाता। श्री यादव ने कहा कि आंदोलन के दौरान किसान

शहीद हुए, उनकी जान गई, झूठे मुकदमे लगे, भाजपा के लोगों ने किसानों को अपमानित किया लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। अंत में वोट के लिए भाजपा ने काले कानून वापस ले लिए।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जो कल तक काले कानूनों के पक्ष में थे, वही अब कह रहे हैं कि किसान हित में कानून वापस लिए गए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के घोषणापत्र में हम शामिल करेंगे कि सभी फसलों की एमएसपी दी जाएगी और गन्ना किसानों का 15 दिन में भुगतान कराया जाएगा, उसके लिए सरकार एक रिवाल्विंग फंड बनाएगी। समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर लगाए गए मुकदमों को वापस लिया जाएगा और जिन किसानों की जान गई है उनके परिजनों को 25-25 लाख रुपए

देकर मदद की जाएगी। श्री यादव ने कहा कि हम घोषणापत्र में उन तमाम बिंदुओं को भी रखेंगे, जिनके जरिए इन घोषणाओं को पूरा करेंगे। हम किसानों और अपने नेताओं से अपील करते हैं कि वे सभी 'अन्न संकल्प' से जुड़े और भाजपा को हटाने और हराने में जुटे।

उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 28 जनवरी को अपने चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए श्री अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया श्री जयंत चौधरी के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अन्न की पोटली लेकर संयुक्त रूप से अन्न संकल्प लिया और वादा किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में किसानों के हितों की समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल रक्षा करेंगे।

समाजवादी गुलदस्तों के रंग और निखरे

बुलेटिन ब्यूरो



उ

त्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से ऐन पहले विभिन्न दलों के वरिष्ठ नेताओं के समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाने से पार्टी के पक्ष में माहौल और मजबूत हो गया है। शामिल होनेवालों में कई नेता मौजूदा भाजपा सरकार में मंत्री भी थे। इन नेताओं का अपने समाज में अच्छा जनाधार होने से जहां सत्तारूढ़ भाजपा को तगड़ा झटका लगा है वहीं सपा के पक्ष में सामाजिक समीकरण और ठोस हुए हैं।

दिनांक 14 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व के प्रति आस्था जताते हुए भाजपा सरकार छोड़कर आए

कई मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्रियों, जिला पंचायत सदस्यों, ब्लाक प्रमुखों, ग्राम प्रधानों, आयोगों एवं विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में अपने हजारों समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की।

शामिल होने वालों में पूर्व मंत्री श्रम, सेवायोजन मंत्री एवं विधायक श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, पूर्व मंत्री आयुष एवं विधायक श्री धर्म सिंह सैनी तथा पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री भगवती सागर प्रमुख थे। इनके अलावा विनय शाक्य विधायक एवं पूर्व मंत्री, रोशन लाल वर्मा विधायक, डॉ मुकेश वर्मा विधायक, चौधरी अमर सिंह विधायक, अली यूसुफ अली पूर्व विधायक, रामहेत

भारती पूर्व मंत्री, नीरज मौर्य पूर्व विधायक, हरपाल सैनी पूर्व एमएलसी, बलराम सैनी पूर्व विधायक राजेन्द्र प्रसाद सिंह पटेल पूर्व विधायक, विद्रोही धनपत राम मौर्य पूर्व राज्यमंत्री, अयोध्या पाल पूर्व मंत्री भी सपा में शामिल हुए।

शामिल हुए नेताओं का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि 2022 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा





चुनाव सेमीफाइनल नहीं फाइनल है। जनता बदलाव के लिए तैयार बैठी है। परिवर्तन होना तय है। जनता भाजपा का सफाया करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी और अंबेडकरवादी मिलकर उत्तर प्रदेश में 400 सीटें जीतने का काम करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्री अखिलेश यादव ऊर्जावान, नौजवान और प्रगतिशील विचारों के हैं। उनके साथ मिलकर क्रांति करूंगा। आज का दिन दलितों, पिछड़ों के सम्मान का दिन है। भाजपा ने धोखा दिया है। उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। श्री स्वामी प्रसाद ने कहा कि लोहिया जी के समाजवाद और अंबेडकरवाद को बचाना पहला कर्तव्य है। श्री धर्म सिंह ने कहा कि फिर से यूपी में समाजवाद कायम करना है।

पूर्व वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री दारा सिंह चौहान एवं डॉ. आर. के. वर्मा सदस्य विधानसभा ने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के समक्ष दिनांक 16 जनवरी को सपा की सदस्यता ग्रहण की। श्री चौहान भाजपा छोड़कर और श्री वर्मा अपना दल छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए।

श्री दारा सिंह के साथ बसपा और भाजपा के कई पदाधिकारी भी समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। विधायक डॉ० आर.के. वर्मा 'अपना दल' के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। उनके साथ बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी सपा में शामिल हुए।

दिनांक 3 जनवरी को श्री राकेश पाण्डेय पूर्व सांसद अम्बेडकर नगर, माधुरी वर्मा भाजपा विधायक बहराइच, कांति सिंह पूर्व सदस्य विधान परिषद, सैय्यदा खातून पूर्व प्रत्याशी



बसपा डुमरियागंज, ब्रजेश मिश्रा पूर्व विधायक भाजपा प्रतापगढ़ समेत विभिन्न दलों के दर्जनों प्रमुख नेता सपा में शामिल हुए।

दिनांक 13 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में भरोसा करते हुए बसपा छोड़कर मेरठ, गाजियाबाद के कई वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। इनमें प्रमुख थे सर्वश्री राम प्रसाद प्रधान, पूर्व राज्यमंत्री, श्री मुकेश कुमार पूर्व राज्यमंत्री तथा श्री सिंहराज मुख्य कोआर्डिनेटर बसपा मेरठ मण्डल तथा पूर्व पार्षद गाजियाबाद नगर निगम।

दिनांक 22 जनवरी को समाजवादी पार्टी की नीतियों एवं श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व पर आस्था जताते हुए बरेली के पूर्व सांसद श्री प्रवीण सिंह ऐरन, बरेली की पूर्व मेयर श्रीमती सुप्रिया ऐरन और हरदोई सण्डीला से पूर्व विधायक स्वर्गीय महावीर सिंह की पत्नी श्रीमती रीता सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले दिनांक 4

जनवरी को वाराणसी की पूर्व विधायक श्रीमती राबिया कलाम ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जबकि दिनांक 6 जनवरी को बदायूं के शेखूपुर विधानसभा के पूर्व बसपा प्रत्याशी काजी मोहम्मद रिजवान एवं अली हमजा चैयरमैन आलापुर ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पूर्व सांसद बदायूं धर्मेन्द्र यादव उपस्थित रहे।

उधर दिनांक 5 जनवरी को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से भाकपा (माले) के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट कर कहा कि श्री अखिलेश यादव की समावेशी राजनीति और राजनीतिक सोच मौजूदा समय में बेहद जरूरी है। प्रतिनिधिमंडल में श्री दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव भाकपा (माले), सुधाकर यादव राज्य सचिव एवं रामजी राय शामिल थे।



समाजवादी गठबंधन की साझा रणनीति





स

माजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दिनांक 12 जनवरी को विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक की जिसमें उत्तर प्रदेश के विकास और भविष्य पर चर्चा के साथ चुनावी रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ। बैठक में श्री शिवपाल सिंह यादव तथा आदित्य यादव (प्रसपा) ओमप्रकाश राजभर (सुभासपा), मसूद अहमद (रालोद) संजय चौहान (जनवादी पार्टी 'सोशलिस्ट') केशव देव मौर्य (महान दल) श्रीमती कृष्णा पटेल (अपना दल कमरावादी) एवं के.के. शर्मा (एन.सी.पी.) शामिल थे।

बैठक में किसानों की खुशहाली, नौजवानों को रोजगार, महंगाई पर रोक, स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा व्यवस्था में सुधार, कानून व्यवस्था में सुधार, व्यापारियों की सुरक्षा, स्वच्छ शुद्ध पेयजल, गरीबों को पेंशन, महिलाओं का सम्मान, उद्योग एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर में विस्तार, नदियों की सफाई और विकास के अन्य आयामों पर भी सार्थक विचार सामने आए। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि मतदाताओं से सीधा सम्पर्क कर कार्यकर्ता हर दरवाजे पर जाकर गठबंधन की सरकार बनाने का आग्रह करेंगे। जनता के साथ सीधा संवाद कायम होगा।

श्री अखिलेश यादव ने इस अवसर पर

कहा कि लोकतांत्रिक, समाजवादी और सामाजिक सद्भाव की पक्षधर ताकतों को एक साथ जोड़ रहे हैं। राज्य की जनता भाजपा से ऊब चुकी है। गठबंधन विकास, सद्भाव और न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। भाजपा की बांटने और अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इंकलाब होगा।

श्री यादव ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में राजनीति की बड़ी लड़ाई लड़ी जानी है। यह लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। सामाजिक न्याय की पक्षधरता के साथ आरक्षण विरोधी ताकतों का प्रतिरोध करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों को धोखा दिया है। 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। तीन काले कृषि कानूनों को जनमत के दबाव में वापस लेने के बावजूद भाजपा की नीयत में अभी भी खोट है। नौजवानों को भाजपा ने बेरोजगारी के दलदल में धकेल दिया है। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में लिखे एक भी वादा को पूरा नहीं किया है।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा का एजेण्डा कुछ ऐसा है कि जनता के हित में कोई काम नहीं होने पाए। भाजपा ने प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था और इलाज-पढ़ाई की तबाही की है। जनता उसके खिलाफ अब चुनाव में अपना फैसला सुनाएगी और समाजवादियों एवं अम्बेडकरवादियों को ही चुनेगी।

समाजवादियों की ताकत सत्यमेव जयते





अरुण कुमार त्रिपाठी

वरिष्ठ पत्रकार

पां

च राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के साथ चुनाव आयोग ने कोरोना (ओमीक्रोन) (और सत्ता) के डर के नाते रैलियों को वर्चुअल कर दिया है। इससे सत्ता और संसाधन से संपन्न भाजपा तो खुश है लेकिन भाजपा की अपार डिजिटल शक्ति का हवाला देते हुए जानकारों का अनुमान है कि इससे चुनाव के लिए बराबरी का धरातल नहीं मिलेगा और विपक्ष नुकसान की स्थिति में होगा।

निश्चित तौर पर विपक्ष और सच्चाई और न्याय के लिए संघर्ष करने वाली जनता के लिए इस तरह की चिंता करना वाजिब है। लेकिन क्या इस तरह की चिंता करके हार मान लेना और हताश हो जाना वाजिब है। नहीं बिल्कुल नहीं। आखिरकार मानव इतिहास में अन्याय करने वाली ताकतों ने कब बेहतर संचार माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को परेशान नहीं किया। ऐसा सदैव रहा है कि न्याय के लिए लड़ने वालों के पास संचार और युद्ध के कमजोर शस्त्र रहे हैं।

चाहे वह रामायण का पौराणिक युग रहा हो चाहे भारत का स्वाधीनता संग्राम रहा हो।

लेकिन विजय उन्हीं की होती है जो सत्य पर अडिग रहते हैं। संघी मीडिया और गोदी मीडिया जिस रामकथा और आदर्श को आगे करके अपनी खबरें और विश्लेषण चलाता है उसी रामकथा के भीतर विभीषण और राम के बीच का संवाद एक प्रेरक सीख देता है। रावण को रथ पर आते हुए और तमाम अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित देखकर विभीषण चिंतित हो जाते हैं।

तुलसीदास कहते हैं कि:

रावण रथी विरथ रघुवीरा। देखि विभीषण भयऊ अधीरा ॥

अधिक प्रीत मन भा संदेहा। बंदि चरण कह सहित सनेहा ॥

नाथ न रथ न तनु पद ताना। केहि विधि जितब वीर बलवाना ॥

सुनहु सखा कह कृपानिधाना। जेहि जय होई सो स्यंदन आना ॥

सौरज धीरज जेहि रथ चाका। सत्यकेतु दृढ़ ध्वजा पताका ॥

बल विवेक दम परहित घोर। क्षमा कृपा समता रजु जोरे ॥

अमल अचल मन त्रोन समाना। सम यम नियम सिली मुख नाना ॥

कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। एहि सम विजय उपाय न दूजा ॥

सखा धर्म मय अस रथ जाके जीत को सकै अजय रिपु ताके ॥

महाअजय संसार सोई जीत सकै सो वीर।

जाके अस रथ होई पुनि सुनहु सखा मति धीर ॥

यह सही है कि राम रावण युद्ध में राम की मदद के लिए बाद में देवताओं ने उन्हें अपना दिव्य रथ भेजा लेकिन उससे पहले राम नंगे पैर बिना रथ के ही रावण से लड़ने और उसे पराजित करने का हौसला रखे हुए थे।

1857 की जिस लड़ाई ने अंग्रेजों को यह अहसास दिला दिया था कि एक बार जरूर आप भारत जैसी सभ्यता को कुचल सकते हैं लेकिन यहां आप स्थायी रूप से शासन नहीं कर सकते। क्योंकि यहां अत्याचार, शोषण, भेदभाव और अन्याय से लड़ने के लिए सवर्ण- अवर्ण, हिंदू- मुसलमान, स्त्री- पुरुष, आदिवासी और गैर आदिवासी सभी एक हैं।

हालांकि अंग्रेजों की जीत में टेलीग्राफ जैसी नई संचार व्यवस्था ने बड़ा काम किया लेकिन भारतीयों ने अपने अखबारों और कलम से माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम का संदेश जन-जन तक पहुंचाया और क्रांतिकारियों की संचार व्यवस्था को चलाने के लिए समाज का हर तबका उतर आया उतर आई। पत्रकारों

अजेय नहीं है भाजपा

बुलेटिन ब्यूरो

यह एक मिथक है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी अजेय हैं। अगर कर्नाटक को छोड़ दिया जाए तो भाजपा की लहर हिंदी राज्यों में उसके प्रभाव का नतीजा है। इसके बावजूद भाजपा को हिंदुओं का बहुसंख्यक वोट भी कभी नहीं मिला। उन्हें ज्यादा से ज्यादा तीस प्रतिशत हिंदुओं का वोट ही मिला है। भाजपा को संसदीय चुनाव में बहुमत इसलिए मिला क्योंकि एक ओर कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय विकल्प के रूप में अपने को प्रस्तुत नहीं कर पाई। उसके अलावा बाकी दलों के बीच भाजपा के विरुद्ध एकता कायम नहीं हो पाई। उनको संसद में इसलिए बहुमत मिला क्योंकि हिंदी इलाकों की आबादी ज्यादा है और इसीलिए वहां सीटें ज्यादा हैं।



फोटो स्रोत : गूगल

और लेखकों ने तो बड़ी तादाद में कुर्बानियां दीं हैं। उनमें मौलवी मोहम्मद बाकर जैसे दिल्ली उर्दू अखबार के संपादक और पयामे आजादी के संपादक अजीमुल्ला खान को कौन नहीं जानता।

महात्मा गांधी ने जब दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे भेदभाव के विरुद्ध अपना अखबार 'इंडियन ओपीनियन' निकाला तो वे जानते थे कि अंग्रेजों के संचार तंत्र के समक्ष उनके अखबार की कोई हैसियत नहीं होने वाली है। लेकिन उनके उस अखबार में न सिर्फ भारतीयों ने साथ दिया बल्कि अंग्रेजों और यहूदियों सभी ने मदद की। उनके अखबार की ताकत संसाधन और आधुनिक मशीनें नहीं थीं। उनके अखबार

'शस्त्रमेव जयते' का बोलबाला उस समय भी था लेकिन गांधी ने युद्ध कला में कुशल अंग्रेजों को यह बता दिया था कि सच्चाई की ताकत हिंसा और झूठ की ताकत से बड़ी है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी सत्य की वही शक्ति और विश्वास लेकर भारत आए थे

की ताकत 'सत्यमेव जयते' थी।

'शस्त्रमेव जयते' का बोलबाला उस समय भी था लेकिन गांधी ने युद्ध कला में कुशल अंग्रेजों को यह बता दिया था कि सच्चाई की ताकत हिंसा और झूठ की ताकत से बड़ी है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी सत्य की वही शक्ति और विश्वास लेकर भारत आए थे और उनका तर्क था कि अगर सत्य की शक्ति से दूसरे देश में लड़ाई जीती जा सकती है तो अपने देश में क्यों नहीं। गांधी की दक्षिण अफ्रीका की पत्रकारिता पर इसाबेल हाफमायर ने पुस्तक लिखी है- गांधीज प्रिंटिंग प्रेस: एक्सपेरिमेंट इन स्लो रीडिंग। जाहिर सी बात है कि अंग्रेजी प्रेस के मुकाबले गांधी की गति बहुत धीमी थी लेकिन उसमें

देश के 11 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा लहर की हकीकत इस प्रकार है।

सिक्किम---0/32

मिजोरम---1/40

तमिलनाडु---4/234

आंध्र प्रदेश---0/175

केरल-----0/140

पंजाब-----3/117

तेलंगाना----3/119

दिल्ली-----8/70

नगालैंड----12/60

ओडिशा---22/147

पश्चिम बंगाल----70/294

जहां पर भाजपा गठबंधन की सरकारें हैं या रही है, उन राज्यों में भी उसकी सीटों की संख्या बहुत प्रभावशाली नहीं है। जैसे कि –

मेघालय----2/60

जम्मू और कश्मीर----25/87

गोवा----27/40

बिहार----74/243

वास्तव में देश भर में भाजपा की लहर एक मिथक है जिसे कुछ पीआर एजेंसियों ने पैदा किया है। आज जो स्थितियां पैदा हो रही हैं वह बताती हैं देश में आने वाले समय में भाजपा को क्षेत्रीय दलों से निरंतर चुनौतियां मिलती रहेंगी। एक प्रकार से नब्बे के दशक की स्थितियां निर्मित हो रही हैं जहां फिर गठबंधन सरकारों का दौर लौट सकता है।



गहराई थी और विवेक था।

सत्य की शक्ति को सिर्फ वे लोग ही नहीं समर्थन देते जो आपके पाले में खड़े होते हैं और अपने पक्षधर होते हैं बल्कि वे लोग भी समर्थन देते हैं जो दूसरे पक्ष में रहते हैं और उन्हें अन्याय के साथ खड़े होने का फायदा मिलता है। भले ही उस समय देश में 'द टाइम्स आफ इंडिया', 'द स्टेट्समैन' जैसे अंग्रेज समर्थक अखबार थे लेकिन बाबें क्रोनिकल जैसा अखबार भी था।

जिसके संपादक बीजी हर्नीमैन ने जलियांवाला बाग कांड को लेकर पूरे ब्रिटेन में तहलका मचा दिया और ब्रिटिश संसद उस पर उद्वेलित हो गई। हर्नीमैन को भारत से निष्कासित किया गया लेकिन उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा।

इसी तरह वेब मिलर जैसे अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड न्यूज के पत्रकार हुए हैं जिन्होंने नमक आंदोलन की खबर को पूरे यूरोप में प्रसारित करके भारत की आजादी की लड़ाई का नैतिक कद बढ़ा दिया। अंग्रेज सरकार ने उन्हें रोकने और विफल करने की बहुत कोशिशें कीं लेकिन उन्होंने धरसाणा नमक फैक्ट्री के सत्याग्रह के समाचार को प्रकाशित कर पूरी दुनिया को बता दिया कि ब्रिटिश सत्ता क्रूर हो गई है और गांधी के सत्याग्रहियों का संयम बना हुआ है।

स्वाधीनता संग्राम में ऐसे तमाम प्रसंग हैं जो बताते हैं कि अपनी बात कहने और अन्याय को उजागर करने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहे राष्ट्रनिर्माताओं को लंबा संघर्ष करना पड़ा बल्कि जो लोग अपने देश की अन्यायी

सामाजिक व्यवस्था से लड़ रहे थे उन्हें भी देशद्रोही, गद्दार और अंग्रेजों का पिढू तक कहा गया। अगर गांधी और तिलक को नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, मराठा और केसरी में लेखन के लिए निशाने पर लिया गया तो डा आंबेडकर को मूकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता, समता और प्रबुद्ध भारत के लिए भी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके अखबार लगातार बंद होते रहे लेकिन वे अपनी बात कहते रहे। डा. राम मनोहर लोहिया को भी जन और मैनकाइंड निकालने के लिए कम पापड़ नहीं बेलने पड़े। आजादी की लड़ाई में विशेषकर जब दूसरे विश्वयुद्ध के समय भारतीयों ने 'भारत छोड़ो' आंदोलन चलाया तो उन्हें ताकतवर प्रचार तंत्र रेडियो का सामना करना



फोटो स्रोत : गूगल

पड़ा। उसके जवाब में डा लोहिया, अच्युत पटवर्धन, अरुण आसफ अली जैसे समाजवादियों ने भूमिगत रेडियो चलाया। इंदिरा गांधी ने आपातकाल में और राजीव गांधी ने अपने शासन काल में मीडिया को नियंत्रित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 1977 में जब चुनाव हुआ तो आपातकाल पूरी तरह से उठा नहीं था। लेकिन जनता ने अपने जनमत से उन लोगों को सत्ता से हटा दिया जिन्हें सब कुछ नियंत्रित करने का गुरुर था। उसी तरह की चुनौती का सामना करते हुए मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने भी 1993 में सपा और बसपा की सरकार बनाई

दरअसल वर्तमान मीडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों का सम्मान करते हैं। उनके लिए पिछड़ों दलितों का उभार एक प्रकार से खलनायकों का उभार है।

और बाद में भी अपना जनाधार बढ़ाते रहे। देश के एक बड़े अखबार ने इन दोनों के बारे में और उनकी पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं लिखा। लेकिन उन्होंने कभी हल्ला बोल आंदोलन चलाकर तो कभी उसकी उपेक्षा करके अपनी लोकतांत्रिक जमीन बनाई और एक नई राजनीति खड़ी की। दरअसल वर्तमान मीडिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो सामाजिक न्याय और मौलिक अधिकारों का सम्मान करते हैं। उनके लिए पिछड़ों दलितों का उभार एक प्रकार से खलनायकों का उभार है। वे उन्हें भ्रष्ट साबित करते हैं, जातिवादी बताते हैं, डकैत बताते हैं और चरित्रहीन बताते हैं।



फोटो स्रोत : गूगल

निश्चित तौर पर आज डिजिटल मीडिया की चुनौती बड़ी है। डिजिटल मीडिया की शक्ति को युआल नोवा हरारी ने अपनी सेपियन्स, होमोडियस और 21 लेशन्स फार ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में विस्तार से व्यक्त किया है। उनका तो कहना है पूंजीवाद और साम्यवाद में फर्क यही है कि पूंजीवाद में डाटा विकेंद्रीकृत होते हैं और साम्यवाद में वे केंद्रीकृत होते हैं। वे डाटा रिलीजन की बात करते हैं। यानी अब जिसके पास डाटा और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर नियंत्रण होगा उसी का दुनिया पर नियंत्रण होगा। इस माध्यम पर बहुत सारा काम हो रहा है। इसे मनुष्य की निजता में घुसपैठ से रोकने और राजनीति को जोड़ तोड़ से संचालित करने में लोग सक्रिय हैं। निश्चित तौर पर डिजिटल प्लेटफार्म की जोड़तोड़ से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का एक

बार का चुनाव जीत सकते हैं और ब्रेजिट जैसी घटना हो सकती है लेकिन वैसा हमेशा नहीं होगा। क्योंकि ब्रेजिट को लागू करने में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जानसन को पसीने छूट रहे हैं और आखिरकार अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के झूठ और अहंकार को पराजित करके जो बाइडेन चुन ही लिए गए। हाल में संपन्न हुए देश और दुनिया के सबसे बड़े किसान आंदोलन ने दिखा दिया है कि शक्तिशाली गोदी मीडिया से सामने तमाम तरह की बदनामी और दुष्प्रचार सहकर कैसे सत्य की लड़ाई को जीता जा सकता है। मौजूदा स्थिति में समाजवादी कार्यकर्ताओं के लिए सावधान होने, सक्रिय होने और ज्यादा चालाक होने की जरूरत है लेकिन निराश होने की कतई जरूरत नहीं है। मानव

इतिहास, भारतीय आजादी के संघर्ष का इतिहास और भारतीय लोकतंत्र का 75 वर्षों का इतिहास ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है कि जो लोग न्याय और सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं वे संचार के कमजोर संसाधनों के बावजूद विजय हासिल करते हैं। बस उनकी दृढ़ता में कमी नहीं आनी चाहिए। वही जीतेंगे जो सत्यमेव जयते में यकीन करते हैं न कि वे जो डिजिटल मेव जयते में विश्वास करते हैं।



पोस्टल बैलेट नई व्यवस्था में सतर्क रहें कार्यकर्ता



पो

स्टल बैलेट उन मतदाताओं के लिए सुविधा है जो किसी

मतदान के मामले में अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत है ताकि सत्तारूढ़ दल कोई बेजा लाभ न ले सके।

भी कारणवश मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। मगर, उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के दौरान जिस तरह से पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करने वालों का दायरा बढ़ा है और इस वजह से ऐसे वोटर्स की संख्या बढ़ी है उससे कई तरह की शंकाएं-आशंकाएं जन्म ले रही हैं। लिहाजा कार्यकर्ताओं को पोस्टल बैलेट से

अतीत गवाह है कि पोस्टल बैलेट की गिनती हमेशा से विवाद में रही है। इतने बड़े पैमाने पर पोस्टल बैलेट की गिनती में पक्षपात की गुंजाइश को चुनाव आयोग रोकेगा कैसे और इसे रोकना सुनिश्चित कैसे करेगा? पोस्टल बैलेट से मतदाताओं की बढ़ी संख्या के बीच चुनाव नतीजों के प्रभावित होने का खतरा भी रहेगा। यह खतरा राजनीतिक दलों,



प्रेम कुमार
वरिष्ठ पत्रकार

खासकर विपक्षी दलों के लिए चिंता का सबब है।

सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो प्रदेश में 5 जनवरी को जारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के आधार पर 80 वर्ष से अधिक आयु के 24,03,296 और 10,64,266 दिव्यांग मतदाता हैं। दोनों मिलाकर करीब 35 लाख मतदाता पोस्टल बैलेट से वोट देने के हकदार हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि कोविड पॉजिटिव वोटर्स को भी बैलेट पेपर से मतदान करने की सुविधा दी गयी है। ताकि कोविड पॉजिटिव वोटर जो आइसोलेशन में हैं उन्हें मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाए और उनके लिए वोटिंग सुनिश्चित कराया जाए। मगर, ये मतदाता सुरक्षित, निर्भिक और गोपनीय मतदान कर सकेंगे- इसकी गारंटी भी होना जरूरी है।

अभी यह नहीं पता है कि कितने कोविड पॉजिटिव लोग पोस्टल बैलेट के हकदार होंगे। नोटिफिकेशन के पांच दिन के भीतर तक पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म 12 डी डाउनलोड करना और ब्लॉक लेवल ऑफिसर की मदद से उसे भरकर जिला निर्वाची पदाधिकारी तक जमा कराना जरूरी है। यह लेख लिखे जाने तक प्रदेश में करीब एक लाख एक्टिव कोविड पॉजिटिव केस थे। लिहाजा 80 साल से अधिक उम्र के मतदाता, दिव्यांग मतदाता और कोविड के कारण आइसोलेशन में रहने वाले अनुमानित मतदाताओं की कुल संख्या तकरीबन 35 से 40 लाख हो जाती है।

चुनाव आयोग ने 14 जनवरी 2020 को ही एक दिशा निर्देश निकाला जिसके तहत न सिर्फ मतदान के दिन ड्यूटी पर रहने वाले पत्रकारों को पोस्टल बैलेट से मतदान करने

का अधिकार मिला है बल्कि इस दायरे में कई विभागों के कर्मचारी भी ला दिए गये हैं। चुनाव आयोग का यह कदम चौंकाने वाला है क्योंकि पहले चरण के मतदान के लिए नोटिफिकेशन की तारीख भी 14 जनवरी ही थी और उसी दिन से उन सात दिनों की गिनती होनी है जब पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। यानी चुनाव आयोग ने एन वक्त पर आखिरी समय में पत्रकारों और 11 विभागों के कर्मचारियों को बैलेट पेपर से मतदान करने के काबिल बनाया।

सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो प्रदेश में 5 जनवरी को जारी मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के आधार पर 80 वर्ष से अधिक आयु के 24,03,296 और 10,64,266 दिव्यांग मतदाता हैं। दोनों मिलाकर करीब 35 लाख मतदाता पोस्टल बैलेट से वोट देने के हकदार हैं।

नज़र डालते हैं उन 11 विभागों पर, जिन्हें पोस्टल बैलेट से वोट करने की छूट दी गयी है- खाद्य आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, आकाशवाणी, दूरदर्शन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवे,

बीएसएनएल, बिजली, स्वास्थ्य, विद्युत सेवा और नागरिक उड्डयन। ये विभाग भी पहले से थे और पत्रकार भी ड्यूटी भी करते रहे हैं और वोट भी डालते रहे हैं। वोट वाले दिन किसी भी वोटर को यह अधिकार होता है कि वह वोट देने के लिए आधे दिन की छुट्टी ले। चाहे तो वह पूरे दिन की भी छुट्टी ले सकता है अगर मतदान केंद्र और कार्यस्थल में दूरी हो। आखिर इतनी बड़ी संख्या में विभागों और उनके कर्मचारियों को पोस्टल बैलेट के दायरे में लाने का फैसला अचानक क्यों हुआ? ऐसे मतदाताओं संख्या कितनी होगी, इसका आकलन भी चुनाव आयोग के पास नहीं है। यह आवेदन आने के बाद ही पता चल सकेगा।

अगर एक जिले में चुनाव आयोग द्वारा चिन्हित नये 11 विभागों के कर्मचारियों की संख्या का आकलन करें तो यह 11 हजार से कम नहीं हो सकती। चलिए, पोस्टल बैलेट की श्रेणी में आने वाले पत्रकारों को भी इसी संख्या में शामिल कर लेते हैं क्योंकि वास्तव में फील्ड में रहने वाले मान्यता प्राप्त पत्रकार कम ही होंगे। फिर भी 75 जिलों में यह संख्या 8 लाख 25 हजार हो जाती है। अब ऊपर की गयी गिनती में इसे जोड़ दें तो पोस्टल बैलेट से वोट देने वालों की तादाद करीब 48 लाख हो जाती है।

उत्तर प्रदेश में पहले से ही करीब पौने दो लाख सैनिक वोटर हैं जो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल करते रहे हैं। इन्हें भी जोड़ लें तो पोस्टल बैलेट के वोटर्स की संख्या करीब 50 लाख हो जाती है। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस तरह हर विधानसभा में औसतन 12 हजार मतदाता पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे।

पोस्टल बैलेट से वोट करने वालों के आंकड़े

आयोग चुनाव में पक्षपात रोके

बुलेटिन ब्यूरो



स

माजवादी पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग से मांग की है कि आयोग विधानसभा चुनाव स्वतंत्र एवं

निष्पक्ष ढंग से सम्पन्न कराए।

इधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से मांग की है कि भाजपा सरकार के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले अधिकारियों को हटाया जाए। उन्होंने आयोग से यह भी कहा कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल के तहत गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से आने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं को रोके और जो लोग यहां आ गए हैं उन्हें वापस भेजे। ये लोग यहां ट्रेनिंग लेकर अफवाह फैलाने, पैसा बांटने, झूठ और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इससे निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव प्रभावित हो रहा है।

इस बाबत समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री राजेन्द्र चौधरी ने 18 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को पत्र लिखकर कहा है कि गुजरात सहित अन्य राज्यों के बाहरी लोग बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों की विधान सभाओं में चुनाव को प्रभावित करने में

संलग्न हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए और ऐसे लोगो को उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए। पूर्व आईपीएस असीम अरूण तथा उनके साथ पिछले पांच वर्षों से तैनात रहे अधिकारियों और पुलिस विभाग के महत्वपूर्ण लोगो की जांच की जाए तथा चुनाव के दौरान पदों से मुक्त किया जाए और ऐसे लोगों पर तत्काल रोक लगाई जाए। जांच करके संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

मुख्य चुनाव आयुक्त के संज्ञान में लाया गया है कि समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों और कार्यालय पर पूरी पाबन्दी लगा दी गई है और गाड़ियों के चालान किये जा रहे हैं, जबकि सत्तारूढ़ दल भाजपा के मंत्री, विधायक, नेता और कार्यकर्ता खुलेआम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन का सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं।

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग की है। श्री पटेल ने मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए।

समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन देकर मांग की है कि 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं की सूची विधानसभा वार, मतदेय स्थलवार उपलब्ध कराई जाय। ऐसे मतदाताओं की संख्या करीब 40 लाख है। सपा ने यह मांग भी की है कि मतगणना समाप्त हो जाने के बाद यदि किसी प्रत्याशी द्वारा वीवीपैट के 50 प्रतिशत से अधिक वीवीपैट की गणना दोबारा कराये जाने की मांग की जाती है तो उस पर अनिवार्य रूप में दोबारा वीवीपैट की गणना कराई जाए।

की विश्वसनीयता को समझने के लिए सिर्फ एक जिले का उदाहरण रखते हैं। अंबेडकर नगर जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं। यहां सेवारत सैनिक मतदाता 2179, दिव्यांग मतदाता 13,879 और 80 साल से अधिक के बुजुर्ग मतदाता 34,027 हैं। यानी पांच विधानसभा में कुल 50,085 पोस्टल मतदाता हुए। प्रति विधानसभा संख्या हुई 10 हजार से थोड़ा ज्यादा।

मगर, इस गिनती में न तो पलकार शामिल हैं, न कोविड मरीज और न ही 14 जनवरी को चुनाव आयोग की ओर से चिन्हित किए गये 11 विभागों के कर्मचारी मतदाता ही शामिल हैं। यह गिनती किसी भी जिले में 25 हजार से कम नहीं हो सकती। इस तरह पांच विधानसभा वाले अंबेडकर नगर में वास्तव में 15 हजार पोस्टल बैलेट हो जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में 77 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां 2017 में 10 हजार से कम वोटों के अंतर से हार-जीत का फैसला हुआ था। इनमें 36 सीटें भाजपा ने जीती थीं, तो 22 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीतीं थीं। बसपा ने 14, कांग्रेस ने 2 और छोटे दलों ने 3 सीटें जीतीं थीं। यूपी में 47 सीटें ऐसी थीं जहां 5

हजार से कम वोटों के अंतर से जीत-हार तय हुई थी। अगर 15 हजार वोटों के अंतर की बात करें तो ऐसी सीटों की संख्या डेढ़ सौ पार हो जाती है।

आंकड़ों के संदर्भ में प्रति विधानसभा 15 हजार औसतन पोस्टल बैलेट की अहमियत बढ़ जाती है। पोस्टल बैलेट की गिनती के समय अवैध मत को लेकर झिंकझिंक आम बात है। पोस्टल बैलेट की गिनती मतगणना के समय शुरू में करने की परंपरा भी बदली जाती रही है। इसकी दोबारा गिनती कराने को लेकर भी विवाद सबसे ज्यादा हुए हैं

उपरोक्त आंकड़ों के संदर्भ में प्रति विधानसभा 15 हजार औसतन पोस्टल बैलेट की अहमियत बढ़ जाती है। पोस्टल बैलेट की गिनती के समय अवैध मत को लेकर झिंकझिंक आम बात है। पोस्टल बैलेट की गिनती मतगणना के समय शुरू में करने की परंपरा भी बदली जाती रही है। इसकी दोबारा गिनती कराने को लेकर भी विवाद सबसे ज्यादा हुए हैं।

आम तौर पर विपक्ष द्वारा सत्ता पर यह आरोप लगता रहा है कि वह प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करते हुए पोस्टल बैलेट के जरिए ही चुनाव नतीजे को प्रभावित करते हैं। बिहार में हुए विधानसभा चुनाव इसके उदाहरण हैं जहां करीब 10 सीटें पोस्टल बैलेट की गिनती से प्रभावित हुए थे। इस पृष्ठभूमि में पोस्टल बैलेट के दायरे में हुई अप्रत्याशित बढ़ोतरी जहां चुनाव आयोग के लिए चुनौती है वहीं विपक्षी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का सबब भी।

(यह लेखक के अपने विचार हैं)



UP चुनाव में EC देगा घर से वोट देने की सुविधा

कैसे मिलेगी सुविधा?

80 साल से ऊपर के बुजुर्गों, दिव्यांगों और कोरोना से प्रभावित लोगों को

वोट देने के लिए क्या जरूरी?

पोलिंग टीम की ओर से दिए गए फॉर्म-12डी को भरकर देना होगा

कैसे पारदर्शी होगी प्रक्रिया?

चुनाव आयोग घर से वोट लेने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराएगा



फोटो स्रोत : गूगल

सच का आईना

भाजपा राज में बढ़ गई बेरोजगारी



फोटो स्रोत : गूगल

प्रेम कुमार

वरिष्ठ पत्रकार

क

भी बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का दावा तो कभी अपनी सरकार में बेरोजगारी दर कम होने का दावा। कभी रोजगार मिशन चलाकर 50 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का दावा किया तो बाद में वे इस विषय पर चुप्पी लगा बैठे। सच यह है कि योगी आदित्यनाथ की

सरकार में सबसे बुरी स्थिति रोजगार की ही रही। न नए रोजगार के मौके बने और न ही पुराने रोजगार को बचाए रखा जा सका। नतीजा यह है कि पांच साल बाद रोजगार करने वालों की संख्या घट चुकी है।

5 साल में घट गये 16.13 लाख नौकरी करने वाले

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का दावा है कि

साढ़े चार साल में सरकार ने साढ़े चार लाख लोगों को रोजगार दिया है। दावा यह भी है कि पिछली किसी सरकार ने यह कामयाबी नहीं दिखलायी। लेकिन, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकॉनमी यानी सीएमआईई ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे की पोल खोलकर रख दी है। सीएमआईई की रिपोर्ट के मुताबिक बीते पांच साल में उत्तर प्रदेश में नौकरी करने वालों की तादाद 16

बेरोजगार छात्रों पर टटा कहर, पुलिसवालों ने हॉस्टल में खीचकर पीटा, आधा दर्जन लॉजों में की तोड़फोड़

छात्रों को दौड़ाकर पीटा, बंदूक के कुंदे से तोड़े कमरों के दरवाजे

प्रस्तावित 10वीं सीएमए



1500 छात्रों पर फेर, लखनऊ के हिन्दुस्तान कॉलेज वाले छात्रों पर कहर बरसाने लगे पुलिस... 10वीं सीएमए पर विरोध... छात्रों को दौड़ाकर पीटा... बंदूक के कुंदे से तोड़े कमरों के दरवाजे...



लॉज के कमरों में दरवाजा तोड़कर घुसी पुलिस, की पिटाई

छोटा बघाड़ा में निकाला जलूस, रोकी ट्रेन, कारवाई के विरोध में छात्रों ने किया पथराव

उत्तर प्रदेश में लखनऊ के हिन्दुस्तान कॉलेज के छात्रों पर कहर बरसाने लगे पुलिस... छात्रों को दौड़ाकर पीटा... बंदूक के कुंदे से तोड़े कमरों के दरवाजे... लॉज के कमरों में दरवाजा तोड़कर घुसी पुलिस, की पिटाई...



Advertisement for 'रेलवे भर्ती परीक्षा नतीजों का व्यापक विरोध, इलाहाबाद पुलिस ने लॉज में घुसकर छात्रों को पीटा'. Includes a table with 'जब तक हमें 1:30' and '2:00' and a list of 'छात्रों की संख्या'.

लाख 13 हजार घट गयी है। सीएमआई के आंकड़े का मतलब यह है कि बीते पांच साल में नौकरी के चाहे जितने अवसर बने हों लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि जिनके पास नौकरियां थीं वह भी छिन गयीं। नतीजा यह हुआ कि पांच साल पहले जितने लोग नौकरी में थे उससे भी कम लोग आज नौकरी में हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रोजगार मांगने वालों की संख्या यानी वर्कफोर्स तो लगातार बढ़ती गयी, लेकिन उस मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना तो दूर उल्टे जिनके पास रोजगार थे वह भी छिन गये। अगर हम रोजगार पाने वाले की संख्या देखें तो सितंबर-दिसंबर 2016 में 5 करोड़ 75 लाख 89 हजार लोगों के पास रोजगार था।

अगर हम रोजगार पाने वाले की संख्या देखें तो सितंबर-दिसंबर 2016 में 5 करोड़ 75 लाख 89 हजार लोगों के पास रोजगार था। इसी अवधि के दौरान 2021 में यह संख्या 5 करोड़ 59 लाख 76 हजार रही

इसी अवधि के दौरान 2021 में यह संख्या 5 करोड़ 59 लाख 76 हजार रही। इस तरह पांच साल बाद 16 लाख 13 हजार कम लोग रोजगार में रह गये। योगी राज में 3.16 करोड़ बढ़ गये काम खोजने वाले उत्तर प्रदेश में सितंबर-दिसंबर 2021 में 17 करोड़ 7 लाख 30 हजार की वर्कफोर्स थी। यह वो आबादी है जो रोजगार खोज रही है। यही वर्कफोर्स सितंबर-दिसंबर 2016 में 14 करोड़ 95 लाख 70 हजार थी। इसका मतलब यह हुआ कि 3 करोड़ 1 लाख 60 हजार वर्क फोर्स बढ़ चुका है। यूपी में अगर दिसंबर 2021 में रोजगार की दर 32.79 प्रतिशत है तो यही दर पांच साल

गोरखपुर : सेवायोजन कार्यालय में रजिस्टर्ड 2 लाख बेरोज़गार, मात्र 4.42% को मिला रोज़गार

उत्तर प्रदेश में सक्रिय बेरोज़गारों की संख्या 41 लाख से ज़्यादा है। मगर सेवायोजन कार्यालय की वेबसाइट के अनुसार रिक्त पदों की संख्या सिर्फ़ 1,256 है।

हिंदी न्यूज़ • बिज़नेस • देश के कुल बेरोज़गारों में उत्तर प्रदेश-बिहार की एक चौथाई

देश के कुल बेरोज़गारों में उत्तर प्रदेश-बिहार की एक चौथाई हिस्सेदारी, अधिक पढ़े-लिखों को कम मौके

उत्तर प्रदेश चुनाव: वरूण गांधी का योगी सरकार पर हमला, बोले- प्रदेश में बेरोज़गारी सर्वोच्च स्तर पर, युवाओं को नहीं मिल रही नौकरियां

डिजिटल न्यूज़, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Harendra Chaudhary Updated Thu, 20 Jan 2022 03:26 PM IST

UP Election 2022: भाजपा सरकार ने नौजवानों को सिर्फ़ लाठीचार्ज और बेरोज़गारी का अभिशाप दिया है: अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने गुरुवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश की डबल इंजन सरकार भी नौजवानों को कोरे-आश्वासन देती रही है और भटकाने के लिए झूठे आंकड़ों के विज्ञापन छपवाती है। प्रयागराज में अपने रोजगार के लिए हक की आवाज बुलन्द करने वाले बेगुनाह छात्रों पर पुलिस ने जिस बर्बरता से प्रहार किया वह घोर निंदनीय है।

लक्ष्मण क

Published: January 27, 2022 10:25:05 pm

पहले दिसंबर 2016 में 38.5 फीसदी थी। इसका मतलब यह है आज अगर सौ में 32 लोगों के पास काम है तो 68 लोगों के पास काम नहीं है। पांच साल पहले स्थिति यह थी कि सौ में 38 लोगों के पास काम थे तो 62 लोगों के पास काम नहीं थे। इस तरह बीते पांच साल में 5.71 प्रतिशत रोजगार घट गये। अगर सरकार ने केवल रोजगार की उस दर को बनाए रखा होता जो 2016 में था तो आज तस्वीर अलग होती। इस दौरान कम से कम 1 करोड़ लोगों को नौकरी मिल चुकी होती।

योगी आदित्यनाथ ने 17 सितंबर 2021 में कहा था कि उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी की दर 2016 में 17 फीसदी से ज्यादा थी और अब यह घट कर 5 प्रतिशत के स्तर पर आ गयी है। सच्चाई क्या है? योगी आदित्यनाथ 2016 के आंकड़े से तुलना क्यों कर रहे हैं? वजह साफ़ है कि अखिलेश यादव के

मुख्यमंत्री रहते मई-अगस्त 2016 में बेरोज़गारी दर 16.82% से गिरकर मई-अगस्त 2017 तक 3.75 प्रतिशत के स्तर पर आ चुकी थी। जाहिर है कि बेरोज़गारी कम करने का श्रेय अखिलेश यादव को जाना चाहिए तो उल्टे योगी आदित्यनाथ उसका श्रेय खुद ले रहे हैं।

सच्चाई यह है कि जब योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री का पद संभाला तब मई-अगस्त 2017 में बेरोज़गारी दर 3.75 के स्तर पर आ चुकी थी। यह बेरोज़गारी लगातार बढ़ती चली गयी। मई-अगस्त 2021 के दौरान यह 5.41 प्रतिशत पर बनी रही थी। स्पष्ट है कि योगी राज में रोजगार की स्थिति खराब हुई और बेरोज़गारी की दर पहले से बदतर हुई। यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि सितंबर-दिसंबर 2018, जनवरी-अप्रैल 2019, मई-अगस्त 2019 के दौरान बेरोज़गारी दर क्रमशः 8.12%, 9.59%

और 10.76% के स्तर तक बेलगाम हो चुकी थी। जनवरी-अप्रैल 2020 को यह 11.8 फीसदी के स्तर पर जा पहुंची।

योगी सरकार ने नवंबर 2020 में घोषणा की थी कि अगले तीन महीने में यानी मार्च 2021 तक 50 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी।

इसके लिए मिशन रोजगार नामक अभियान चलाया गया। बेरोज़गारों को रजिस्ट्रेशन कराने को कहा गया। मगर, यह अभियान भी फ्लॉप साबित हुआ। अब इस अभियान की कोई चर्चा नहीं करता।

योगी राज में आरक्षण की भी पूरी अनदेखी यूपी सरकार में जो नियुक्तियां हुईं भी उनमें आरक्षण नियमों की भी खूब अनदेखी हुई। 69 हजार बेसिक शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह महज 3.85 प्रतिशत अभ्यर्थियों को आरक्षण मिला।



वहीं, एससी वर्ग को 21 फीसदी की जगह 16.6 फीसदी लोगों को आरक्षण मिला। जब योगी सरकार ने 6 हजार अभ्यर्थियों की नियुक्ति करने और बाकी बचे 17 हजार नियुक्तियां करने का निर्णय लिया और तय किया कि आरक्षण संबंधी गलतियों को सुधारा जाएगा, तब तक यह निर्णय अपना औचित्य खो चुका था। घोषणा के दस दिन बाद ही आचार संहिता लग चुकी है।

गरीबी में यूपी देश में टॉप थ्री पर बेरोजगारी ही नहीं गरीबी में भी उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है। नवंबर 2021 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट से पता चलता है कि बिहार और झारखण्ड के बाद यूपी में सबसे ज्यादा गरीबी है। यहां की 37.79 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रह रही है। उत्तर प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद

69 हज़ार बेसिक शिक्षक भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह महज 3.85 प्रतिशत अभ्यर्थियों को आरक्षण मिला। वहीं, एससी वर्ग को 21 फीसदी की जगह 16.6 फीसदी लोगों को आरक्षण मिला

(एनएसडीपी) भी राष्ट्रीय औसत के आधे से कम है। भारत का एनएसडीपी 95 हजार रुपये प्रति व्यक्ति है तो उत्तर प्रदेश का एनएसडीपी 45 हजार रुपये प्रति व्यक्ति है। जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उनके बीच अगर तुलना करें तो उत्तर प्रदेश का एनएसडीपी गोवा के मुकाबले पौने सात गुणा कम है। उत्तराखण्ड भी यूपी से 3.3 गुणा आगे है जबकि पंजाब की स्थिति उत्तर प्रदेश से 2.64 गुणा बेहतर है।



रामपुर की जनता लड़ रही आजम साहब का चुनाव

समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में शामिल पार्टी के वरिष्ठ नेता व रामपुर के सांसद मोहम्मद आजम खान साहब के खिलाफ भाजपा सरकार का उत्पीड़न भरा रवैया विधानसभा चुनावों में बढ़ा मुद्दा बन रहा है। समाजवादी पार्टी ने आजम साहब को रामपुर विधानसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया है। समाजवादी पार्टी के नेता व कार्यकर्ता क्षेत्र में मजबूती से प्रचार कर रहे हैं।

वे जनता को बता रहे हैं कि कैसे झूठे मामलों में फंसाकर आजम साहब और उनके परिवार के सदस्यों को परेशान किया जा रहा है। रामपुर की सियासत की जानकारी रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि इलाकाई जनता के अधिकांश लोग भी इससे सहमति जता रहे हैं कि आजम साहब के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। ऐसे में इस बात के पूरे आसार हैं कि रामपुर की जनता रिकार्ड मतों से आजम साहब की जीत सुनिश्चित कर यह संदेश देगी कि रामपुर की जनता की अदालत में आजम साहब निर्दोष हैं।

रामपुर की वह जनता जिसके लिए आजम साहब का दिल धड़कता है और जिनकी जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए उन्होंने रामपुर में तमाम विकास कार्य करवाए। इलाकाई लोगों का कहना है कि आजम साहब की चुनाव मैदान में अनुपस्थिति भले हो लेकिन उससे खास फर्क इसलिए नहीं पड़

रहा क्योंकि जनता ही उनका चुनाव लड़ रही है। जनता खुद ही बता रही है और याद कर रही कि आजम साहब ने रामपुर के लिए कितना कुछ किया है। लिहाजा इस बार वोट की चोट कर उनसे हुए अन्याय के खिलाफ जनता अपना विरोध दर्ज करेगी।

रामपुर की सियासत की जानकारी रखने वाले विश्लेषकों का मानना है कि इलाकाई जनता के अधिकांश लोग भी इससे सहमति जता रहे हैं कि आजम साहब के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है

लोगों का कहना है कि एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार के प्रति सियासी बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई कतई बर्दाश्त नहीं जा सकती। लोग सरकार की मनमानी का जवाब चुनावों में वोट के जरिए देने का मन बना चुके हैं।

उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री

अखिलेश यादव कई मौकों पर कह चुके हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं सांसद मोहम्मद आजम खान के साथ जो व्यवहार भाजपा सरकार कर रही है वह अनैतिक एवं अमानवीय है। लोकतंत्र में सरकार का आचरण बिना राग द्वेष का होना चाहिए। भाजपा सरकार द्वारा समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपमानित करने और यातना देने के लिए झूठे केसों में फंसाया जाता रहा है। भाजपा समझती है कि इससे समाजवादी पार्टी का मनोबल तोड़ा जा सकता है। भाजपा इसमें कभी सफल नहीं हो सकेगी।

आजम साहब वह शख्सियत हैं जिन्होंने आपातकाल में दो वर्ष तक जेल की यातना सही। वे 9 बार विधायक, 5 बार मंत्री और एक बार राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं। इस समय वह रामपुर से लोकसभा के सदस्य हैं। उन्होंने तालीम के क्षेत्र में मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में स्थापित कर ऐतिहासिक काम किया।

लिहाजा रामपुर की जनता भी मानती है कि शासन-प्रशासन की हरकतों से आजम साहब का वह शानदार इतिहास नहीं धुल जाएगा जिसमें वे गए कई दशकों से रामपुर और आस-पास की राजनीति का चेहरा बदल देने वाले नायक के तौर पर नजर आते हैं। विधानसभा चुनाव में रामपुर एवं आस-पास की सीटों पर सपा का परचम लहरा कर जनता अपने इलाकाई नायक के लिए जीत का जनादेश देने का मन बना चुकी है। ■■

हमेशा यादों में रहेंगे पंडित सिंह

बुलेटिन ब्यूरो



स

माजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने दिनांक 7 जनवरी को गोंडा में पूर्व मंत्री स्व. पंडित सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। श्री यादव के साथ

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव भी मौजूद रहे। इस अवसर पर सपा अध्यक्ष ने अमर स्मृति कोष का विमोचन किया। दोनों नेताओं ने पंडित सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया।

श्री यादव ने स्व. पंडित सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे गोंडा के लोकप्रिय जन

नेता थे। स्व. पंडित सिंह ने गोंडा और आसपास के क्षेत्रों में पार्टी को मजबूत किया। उनके असमय चले जाने से समाजवादियों ने अपना भरोसेमंद साथी खो दिया है।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को



संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने 5 साल तक कोई काम नहीं किया। समाजवादी सरकार के कार्यों का ही शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब सरकार के आखिरी समय में शिलान्यास का दिखावा कर रही है।

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार

बनने पर गोंडा में मेडिकल कॉलेज बनाएंगे जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। भाजपा सरकार ने कोरोना काल में किसी की मदद नहीं की। बड़ी संख्या में लोग ऑक्सीजन की कमी से मौत के मुंह में चले गए। यह सरकार दवा और बेड का इंतजाम नहीं कर पाई।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में लोगों की नौकरियां चली गईं। आज प्रदेश की जनता किसान, नौजवान और गरीब महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। भाजपा सरकार झूठे विज्ञापन जारी कर जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद कर रही है। प्रदेश की जनता चुनाव का इंतजार कर रही है। इस बार पूरब से पश्चिम तक भाजपा का सफाया होगा।

श्री यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार में लोगों को न्याय मिलेगा। एनसीआरबी का डाटा कहता है कि भाजपा सरकार में ज्यादा दंगे हुए। ज्यादा अपराध हुए। बच्चियों के साथ ज्यादा घटनाएं हुईं। भाजपा सरकार के पास महंगाई, बेरोजगारी का कोई जवाब नहीं है। बड़े-बड़े इन्वेस्टर मीट हुए लेकिन बताइए क्या गोंडा, फैजाबाद से लेकर आसपास कोई कारखाना लगा, कोई रोजगार आया?

श्री यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में डीजल-पेट्रोल, खाद-बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र सभी महंगे हो गये हैं। लोगों की कमाई आधी हो गई और महंगाई दोगुनी हो गई। आने वाले समय में गरीब, किसान,

किसान, मजदूर सभी वर्ग मिलकर भाजपा सरकार को हटाने का काम करेंगे। इससे झूठी सरकार जनता ने कभी नहीं देखी।

श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार ने लैपटॉप बांटे थे, भाजपा सरकार में नहीं बंटे यही फर्क है। समाजवादी सरकार में नौकरी मिलती थी भाजपा सरकार में नौकरी मांगने पर लाठियां मिलती हैं, फर्क साफ है। भाजपा सरकार समाजवादियों से घबरा गई है।

कार्यक्रम में सर्वश्री माता प्रसाद पाण्डेय, नरेन्द्र सिंह, महेश सिंह डॉ सूरज सिंह, अभिषेक सिंह, पूर्व मंत्री अरविन्द सिंह गोप, योगेश प्रताप सिंह, पूर्व मंत्री एस.पी. सिंह, पूर्व मंत्री राम बिशुन आजाद, एवं राम प्रताप सिंह, नदिता शुक्ला आदि की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।



साफ़ और बेबाक

Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

Socialist Leader of India. Chief Minister of UP (2012 - 2017)



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

‘300 यूनिट मुफ्त पाओ’
नाम लिखाओ, छूट न जाओ

सपा व सहयोगियों की सरकार बनने पर 300 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त पाने के लिए शुरू हो रहे ‘नाम लिखाओ अभियान’ में उप्र के घरेलू कनेक्शनवाले परिवार नाम लिखाएं और सपा व सहयोगी दलों की सरकार बनाने के लिए अपना खुला समर्थन व्यक्त करें।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

"सम्पन्नता और समता लाना ही समाजवाद है"

जनसंघर्षों के प्रेरणा पुरुष 'छोटे लोहिया' स्व. जनेश्वर मिश्र जी की पुण्यतिथि पर शत-शत नमन।

[Translate Tweet](#)



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

कभी कहा मथुरा... कभी कहा अयोध्या... और अब कह रहे हैं... गोरखपुर... जनता से पहले इनकी पार्टी ने ही इनको वापस घर भेज दिया है... दरअसल इनको टिकट नहीं मिली है, इनकी वापसी की टिकट कट गयी है।

यूपी कहे आज का
नहीं चाहिए भाजपा

[#बाइस_में_बाइसिकल](#)



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

UPTET परीक्षा में अभ्यर्थियों के साथ हुए अन्याय में सपा साथ खड़ी है।

युवाओं का अनादर भाजपा को बहुत महंगा पड़ेगा। संवेदनहीन भाजपा को यही अभ्यर्थी हर बूथ पर वोटों के लिए तरसा देंगे।

‘युवा’ कहे आजका
नहीं चाहिए भाजपा



Following



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

जनता कहे इंकलाब बा
यूपी में बदलाव बा...
ठाठा बाबा का
अबके बंटाधार बा...

डबल इंजन के
फुस सरकार बा
आपस मा सर फुटव्वल
जूतम पैजार बा...

अबके झूठ के फूलवा का
बगीचा उजाड़ बा...
बाइस में बाइसिकल का
चौचक भौकाल बा...



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

भाजपा का काम ~ अपराधी सरेआम!

बाबा जी अपने करीबी नालबद्ध माफियाओं के
टॉप टेन की सूची बनाकर एक टीम बना लें और
आईपीएल की तरह एक 'एमबीएल' मतलब
'माफिया भाजपा लीग' शुरू कर दें। शहर के
पुलिस कप्तान तो उनके लिए पिच बिछाए बैठे ही
हैं और टीम कप्तान वो खुद हैं ही... हो गए पूरे
ग्यारह.

Translate Tweet



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

'झूठ' का पर्दाफाश होगा
अब यूपी में बदलाव होगा

[#बाइस_में_बाइसिकल](#)

Translate Tweet



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

69000 व नयी भर्ती की मांग कर रहे बेरोजगार
प्रदर्शनकारियों से हमारा आग्रह है कि वो इस
निर्दयी भाजपा सरकार के आगे अब और हाथ न
जोड़ें, न ही उनकी लाठी और उत्पीड़न का शिकार
हों।

हम आपके साथ हैं और आपके सहयोग से जब
हम हर बूथ जीतकर आएं तो सभी लंबित
भर्तियों को पूरा करेंगे।

Translate Tweet



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

10 मार्च को इंकलाब होगा
उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा

[#बाइस_में_बाइसिकल](#)



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

प्रेम और पोषण से भरा एक कुल्हड़ दूध का...
धन्यवाद इस प्यार और समर्थन के लिए।

Translate Tweet



Akhilesh Yadav ✓

@yadavakhilesh

इस बार सभी शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों,
उपेक्षितों का 'मेल' होगा और भाजपा की बाँटने
व अपमान करनेवाली राजनीति के खिलाफ सपा
की सबको सम्मान देनेवाली राजनीति का इंकलाब
होगा।

बाइस में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक
राजनीति का 'मेला होबे'!

भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी!

[#भाजपा_खत्म](#)



हर घर जगमगाएगा हर खेत लहलहाएगा

घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को
300 यूनिट बिजली
समाजवादी सरकार में मुफ्त होगी

किसानों को सिंचाई के लिए
बिजली मुफ्त मिलेगी

अधिक जानकारी के लिए

कृपया लॉग इन करें
www.samajwadiparty.in